Agriculture and Industrial Area of India

B.A. 4th Sem- Minor Elective- Economics

भारत में कृषि क्षेत्र

प्रगति के सुनहरे अतीत पर खड़ा भारतीय कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में सदैव ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। भारत में विश्व का 10वाँ सबसे बड़ा कृषि योग्य भू–संसाधन मौजूद है। वर्ष 2011 की कृषि जनगणना के अनुसार, देश की कुल जनसंख्या का 61.5 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण भारत में निवास करता है और कृषि पर निर्भर है। उक्त तथ्य भारत में कृषि के महत्त्व को भलीभांति स्पष्ट करते हैं। वर्ष 2019 में देश के कृषि क्षेत्र में कई प्रकार के हस्तक्षेप और व्यवधान देखे गए। वर्ष 2019 के पहले हिस्से में 75000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड निवेश के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। हालाँकि वर्ष 2019 का दूसरा हिस्सा इस क्षेत्र के लिये आपदा के रूप में सामने आया और देश के कई हिस्सों में सूखे और बाढ़ की घटनाएँ देखी गईं। इसके अलावा आर्थिक मंदी और सब्जियों खासकर प्याज तथा दालों की कीमतों में वृद्धि ने उपभोक्ताओं (जिसमें किसान भी शामिल हैं) पर बोझ को और अधिक बढ़ा दिया। यह स्थिति मुख्यतः दो तथ्यों को स्पष्ट करती है।

1. लोकलुभावन उपायों और प्रयासों का अर्थव्यवस्था पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है और
2. जलवायु–प्रेरित आपदाओं की भेद्यता को कम करने के कई उपायों के बावजूद कृषि क्षेत्र और किसानों को नुकसान हो रहा है।

इस प्रकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक है कि नीति निर्माण के समय अतीत के अनुभवों को ध्यान में रखा जाए और मौजूदा अवसरों का यथासंभव लाभ उठाया जाए।

भारत में कृषि की मौजूदा स्थिति

हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 के अनुसार भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में रोज़गार अवसरों के लिये कृषि क्षेत्र पर अधिक निर्भर है।

आँकड़ों के मुताबिक देश में चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्द्धन में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का हिस्सा वर्ष 2014–15 के 18.2 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2019–20 में 16.5 प्रतिशत हो गया है, जो कि विकास प्रक्रिया का स्वभाविक परिणाम है।

ज्ञात हो कि कृषि में मशीनीकरण का स्तर कम होने से कृषि उत्पादकता में कमी होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 के अनुसार भारत में कृषि का मशीनीकरण 40 प्रतिशत है, जो कि ब्राज़ील के 75

प्रतिशत तथा अमेरिका के 95 प्रतिशत से काफी कम है। इसके अलावा भारत में कृषि ऋण के क्षेत्रीय वितरण में भी असमानता विद्यमान है।

देश के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिये पशुधन आय का दूसरा महत्त्वपूर्ण साधन है। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी भूमिका महत्त्वपूर्ण है। बीते 5 वर्षों के दौरान पशुधन क्षेत्र 7.9 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है।

कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत अग्रणी स्थान पर है, किंतु विश्व कृषि व्यापार में भारत का योगदान मात्र 2.15 प्रतिशत ही है। भारतीय कृषि निर्यात के मुख्य भागीदारों में अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत से ही भारत कृषि उत्पादों के निर्यात को निरंतर बनाए हुए है।

कृषि क्षेत्र की चुनौती और समस्याएँ

- पूर्व में कृषि क्षेत्र से संबंधित भारत की रणनीति मुख्य रूप से कृषि उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित रही है जिसके कारण किसानों की आय में बढ़ोतरी करने पर कभी ध्यान नहीं दिया गया।

- विगत पचास वर्षों के दौरान हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद, भारत का खाद्य उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा है जबकि जनसंख्या में 2.55 गुना वृद्धि हुई है, किंतु किसानों की आय वृद्धि संबंधी आँकड़े अभी भी निराशाजनक हैं।

- ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है किंतु यह लक्ष्य काफी चुनौतिपूर्ण माना जा रहा है।

- लगातार बढ़ते जनसांख्यिकीय दबाव, कृषि में प्रच्छन्न रोज़गार और वैकल्पिक उपयोगों के लिये कृषि भूमि के रूपांतरण जैसे कारणों से औसत भूमि धारण (स्ंदक भ्वसकपदह) में भारी कमी देखी गई है। आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 1970–71 में औसत भूमि धारण 2.28 हेक्टेयर था जो वर्ष 1980–81 में घटकर 1.82 हेक्टेयर और वर्ष 1995–96 में 1.50 हेक्टेयर हो गया था।

Agriculture and Industrial Area of India

B.A. 4th Sem- Minor Elective- Economics

- उच्च फसल पैदावार प्राप्त करने और कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि के लिये बीज एक महत्त्वपूर्ण और बुनियादी कारक है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करना जितना महत्त्वपूर्ण है, उतना ही महत्त्वपूर्ण है उन बीजों का वितरण करना किंतु दुर्भाग्यवश देश के अधिकतर किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुँच ही नहीं पाते हैं।

- भारत का कृषि क्षेत्र काफी हद तक मानसून पर निर्भर करता है, प्रत्येक वर्ष देश के करोड़ों किसान परिवार बारिश के लिये प्रार्थना करते हैं। प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कभी–कभी किसानों को नुकसान का भी सामना करना पड़ता है, यदि अत्यधिक बारिश होती है तो भी फसलों को नुकसान पहुँचता है और यदि कम बारिश होती है तो भी फसलों को नुकसान पहुँचता है। इसके अतिरिक्त कृषि के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन भी एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आया है और उनकी मौसम के पैटर्न को परिवर्तन करने में भी भूमिका अदा की है।

- आज़ादी के 7 दशकों बाद भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन व्यवस्था गंभीर हालत में है। यथोचित विपणन सुविधाओं के अभाव में किसानों को अपने खेत की उपज को बेचने के लिये स्थानीय व्यापारियों और मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें फसल का सही मूल्य प्राप्त हो पाता।

कृषि का योगदान–

- भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 60: आबादी के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है। भारत में, कृषि कुल जीडीपी का सोलह प्रतिशत (16प्रतिशत) और कुल निर्यात का दस प्रतिशत (10प्रतिशत) योगदान करती है।

- यह केवल आजीविका का स्रोत नहीं है। यह भोजन, चारा और ईंधन का मुख्य स्रोत है। यह देश के आर्थिक विकास का मूल आधार है।

- भारत का 60प्रतिशत से अधिक भूमि क्षेत्र कृषि योग्य है जो कुल कृषि योग्य भूमि के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य के कृषि उत्पादों में चावल, गेहूं, आलू, टमाटर, प्याज, आम, गन्ना, सेम, कपास, आदि शामिल हैं।

Agriculture and Industrial Area of India

B.A. 4th Sem- Minor Elective- Economics

- यदि कृषि नहीं होगी तो सरकार और राष्ट्र सफल नहीं हो पाएंगे। कृषि का अर्थ है फसलों की खेती के साथ–साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग, मछली पालन और वानिकी।

  निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कृषि के महत्व को रेखांकित करते हैं।

  - यह राष्ट्रीय आय में योगदान देता है।
  - वर्तमान में यह राष्ट्रीय आय में लगभग 24.4प्रतिशत का योगदान दे रहा है।
  - यह भोजन का मुख्य स्रोत है
  - हरित क्रांति के बाद हम खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। मुख्य फसलें एक साथ 195 मिलियन टन होती हैं। भारत में लगभग 100 मिलियन टन चावल का उत्पादन किया जाता है। भारत में गेहूं का उत्पादन लगभग 95 मिलियन टन है।
  - यह औद्योगिक विकास में भी योगदान देता है
  - यह सूती वस्त्र, जूट, चीनी, सब्जियां, तेल, टिनयुक्त भोजन, सिगरेट और रबर और कई अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसे उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रदान करता है।

राजस्व के स्रोत

भू–राजस्व, कृषि आधारित औद्योगिक वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, कृषि मशीनरी और उपकरणों के उत्पादन और बिक्री पर कर और सरकार को राजस्व प्रदान करने के कई और तरीके।

प्रभाव

देश के कृषि क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न चुनौतियों और समस्याओं के परिणामस्वरूप किसान परिवारों की आय में कमी होती है और वे ऋण के बोझ तले दबते चले जाते हैं।

निम्न और अत्यधिक जोखिम वाली कृषि आय कृषकों की रुचि पर हानिकारक प्रभाव डालती है और वे खेती को छोड़ने के लिये मजबूर हो जाते हैं।

इससे देश में खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र के भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

Agriculture and Industrial Area of India

B.A. 4th Sem- Minor Elective- Economics

उपाय

- कृषि क्षेत्र समावेशी विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण खंड है और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करता है, खासकर तब जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन न कर रही हो।

- कृषि व्यय और विकास चालकों में असमानता के मुद्दे को संबोधित किया जाना चाहिये। पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में उच्च विकास के बावजूद भी इन क्षेत्रों पर किये जाने वाला व्यय अपेक्षाकृत काफी कम है। अतः पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र के योगदान को देखते हुए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों पर होने वाले व्यय में वृद्धि की जाए।

- कृषि में अनुसंधान और विकास पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत किया जाना चाहिये।

- कृषि पर भारत की निर्भरता और जलवायु–प्रेरित आपदाओं को देखते हुए देशभर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 'क्लाइमेट स्मार्ट विलेज' (ब्सपउंजम ेउंतज टपससंहमे) की अवधारणा के कार्यान्वयन का विस्तार किया जाना चाहिये।

- कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को भी प्रोत्साहन किया जाना चाहिये।

- कृषि क्षेत्र से संबंधित आँकड़ों को एकत्र करने के लिये एक एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिये। यह संस्था लाभार्थियों की पहचान, सब्सिडी के बेहतर लक्ष्यीकरण और नीति निर्माण में सहायक हो सकती है।

Agriculture and Industrial Area of India

B.A. 4th Sem- Minor Elective- Economics

औद्योगिक क्षेत्र

जब कई व्यवसाय एकत्र होते हैं और उनकी निकटता का लाभ उठाते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाते हैं। लाभप्रद भौगोलिक कारकों के कारण, वे विशेष स्थानों पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं।

प्राकृतिक संसाधन, जैसे कोयला या लोहे की चट्टान, या जल स्रोत अक्सर औद्योगिक क्षेत्रों का फोकस होता है। यह सजातीय नहीं हो सकता है, जिसका अर्थ है कि एक ही क्षेत्र में कई असंबंधित प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं, और आमतौर पर रेल जैसी परिवहन धमनियों द्वारा अच्छी तरह से सेवा प्रदान की जाती है।

औद्योगिक क्षेत्र वे स्थान हैं जहां अनुकूल भू–आर्थिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उद्योग केंद्रित हो गए हैं। ये वे स्थान हैं जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा विनिर्माण क्षेत्र में काम करता है, जो बड़े पैमाने पर संचालित होता है

औद्योगिक क्षेत्रों का प्रारंभिक इतिहास

भारत के औद्योगिक क्षेत्रों को सबसे पहले 1944 में ट्रेवार्था और बर्नर द्वारा अलग किया गया था। पीपी करण और डब्ल्यूएम जेनक्रिंस (1959) ने बाद में भारत के औद्योगिक क्षेत्रों को परिभाषित किया।

स्पेंसर और थॉमस (1968), आरएल सिंह (1971), बीएन सिन्हा (1972), एमआर चौधरी (1976), और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) ने भी भारत के औद्योगिक क्षेत्रों (1971, 1982) की पहचान की।

अल्फ्रेड मार्शल ने देशों के औद्योगिक संगठन की कुछ विशेषताओं को संदर्भित करने के लिए सबसे पहले ष्औद्योगिक जिलाष शब्द का उपयोग किया था। एक औद्योगिक जिला (आईडी) एक ऐसा स्थान है जहां प्राथमिक उद्योग और संबंधित उद्योगों में काम करने वाले और रहने वाले लोग ऐसा करते हैं।

1990 के दशक के अंत तक, विकसित और विकासशील दोनों देशों के औद्योगिक जिलों ने औद्योगीकरण और क्षेत्रीय विकास रणनीतियों के बारे में चर्चा में व्यापक रुचि आकर्षित की थी।

Agriculture and Industrial Area of India

B.A. 4th Sem- Minor Elective- Economics

भारत में औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक उन्नति

आर्थिक सिद्धांतों ने किसी राष्ट्र की प्रभावी प्रगति के लिए भारत में एक अच्छे औद्योगिक क्षेत्र पर जोर दिया है। इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्र स्थिर रोजगार प्रदान करता है, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को कम करता है और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है।

इसलिए पाँच पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया , जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों के साथ औद्योगिक आधार का विस्तार करना था।

सरकारी हस्तक्षेप और भारत में औद्योगिक क्षेत्र का विकास

भारत के विकास में औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, स्वतंत्रता के समय, भारतीय उद्योगपतियों के पास बड़े निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी , इसलिए सरकार को भारत में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना पड़ा।

इसके अलावा, समाजवादी सिद्धांतों के प्रति भारत के झुकाव के कारण सरकार को उन उद्योगों पर नियंत्रण करना पड़ा जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे, जिसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी रखा गया था।

ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना लघु उद्योगों का विकास और चुनौतियाँ–

- लघु उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण विकासरू 1955 में, ग्राम और लघु उद्योग समिति (कार्वे समिति) ने भारत में औद्योगिक क्षेत्र में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में लघु उद्योगों की भूमिका पर प्रकाश डाला।
- परिभाषा – लघु उद्योग को किसी उद्योग में अनुमत अधिकतम निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। समय के साथ इस सीमा को संशोधित किया गया है।
- वर्तमान में, अधिकतम निवेश की अनुमति एक करोड़ रुपये है।
- श्रम–गहन वे अधिक श्रम–गहन हैं और इस प्रकार अधिक रोजगार प्रदान करते हैं
- हालाँकि, वे बड़ी औद्योगिक कंपनियों (घरेलू और विदेशी) के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।

Agriculture and Industrial Area of India

B.A. 4th Sem- Minor Elective- Economics

विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद आरक्षण और प्रोत्साहन— इसलिए सरकार ने हस्तक्षेप किया और लघु उद्योगों के लिए उत्पादों की एक निश्चित संख्या आरक्षित कर दी। इसके अलावा, उन्हें कम उत्पाद शुल्क और कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण जैसी रियायतें दी गईं । हालाँकि, आरक्षण नीति को 1997 और 2015 के बीच समाप्त कर दिया गया था, जिसमें कई उत्पादों को आरक्षित सूची से हटा दिया गया था।